BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधार

06 जून, 2026

बॉन्ड मार्केट को मजबूत करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना

वैश्विक निवेश के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर सुधार कर रही है। पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधारों की श्रृंखला पेश की है। प्रमुख उपायों में ब्याज आय, दीर्घकालिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) और अल्पकालिक पूंजी लाभ (एसटीसीजी) पर टैक्स में छूट, पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का विस्तार और निवेश नियमों का सरलीकरण शामिल हैं।

इन सुधारों का लक्ष्य स्थिर दीर्घकालिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने, जी-सेक बाजार को सुदृढ़ करने और निवेशक आधार का विस्तार और विविधीकरण करके भारत के ऋण बाजार को मजबूत करना है। विदेशी भागीदारी बढ़ने से अवसंरचना, निर्माण, शहरी विकास, जलवायु पहलों और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण का स्रोत प्राप्त होगा। यह बाजार तरलता और मूल्य खोज में भी सुधार करेगा, एक अधिक सुचारू उत्पादन रूपरेखा के विकास का समर्थन करेगा, सरकारी उधार लागत को कम करेगा, वित्तीय बाजार के मानकों को मजबूत करेगा और अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के प्रवाह को बढ़ाएगा।

ये सुधार पेंशन कोष, बीमा कंपनियों और संप्रभु संपत्ति कोष जैसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेंगे, जिससे पूंजी प्रवाह में अधिक स्थिरता और निरंतरता आयेगी। इसके अलावा, इन सुधारों से विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने और भारत के वित्तीय बाजारों की सहनीयता को मजबूत करने की भी उम्मीद है।

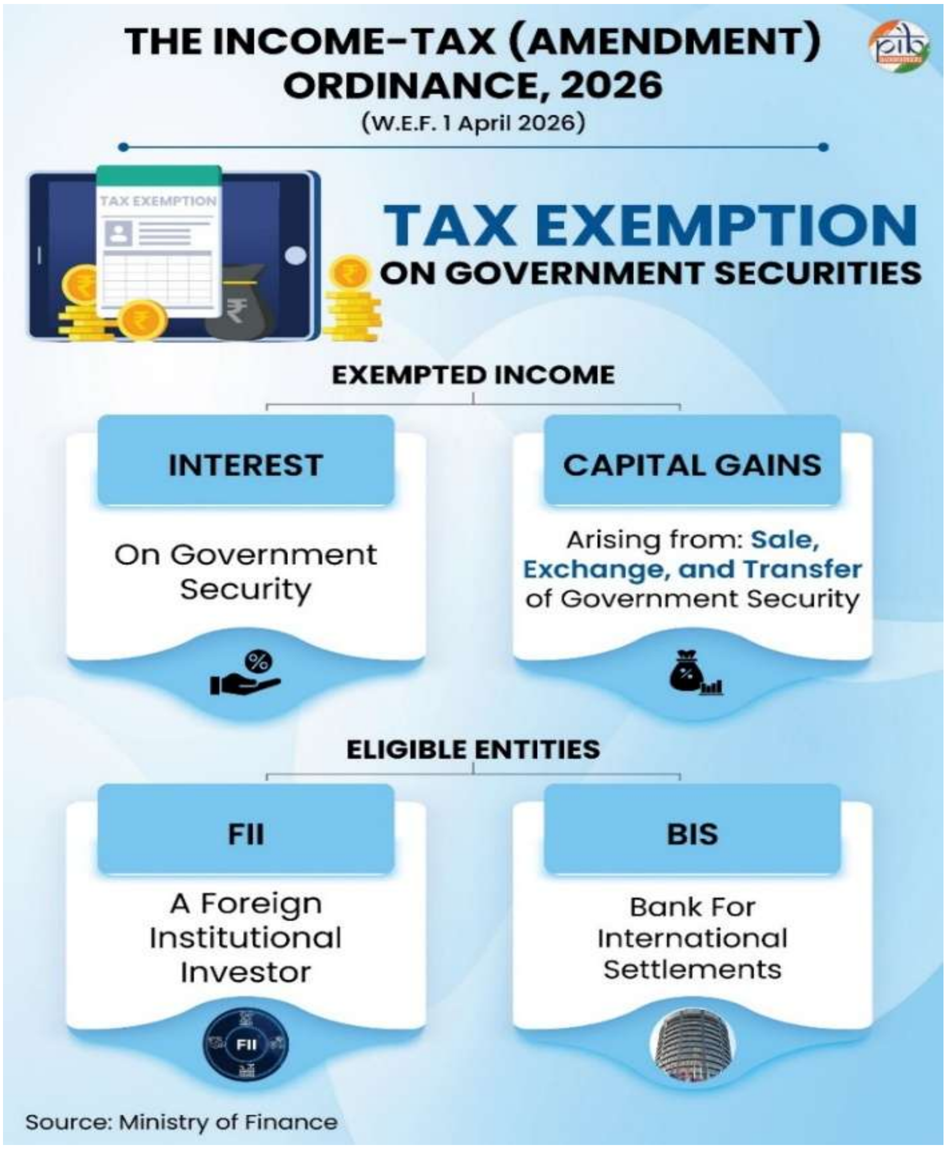
THE INCOME-TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026
(W.E.F. 1 April 2026)
TAX EXEMPTION
TAX EXEMPTION
ON GOVERNMENT SECURITIES
EXEMPTED INCOME
INTEREST
On Government Security
CAPITAL GAINS
Arising from: Sale, Exchange, and Transfer of Government Security
ELIGIBLE ENTITIES
FII
A Foreign Institutional Investor
FII
BIS
Bank For International Settlements
Source: Ministry of Finance

एफआईआई, एफपीआई, जी-सेक, बीआईएस को समझना

विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) एफपीआई की एक श्रेणी है, जो विशेष रूप से म्युचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और हेज फंड जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों का संदर्भ देती है। ये संस्थान वित्तीय बाजारों में एकत्रित निधियों का निवेश करते हैं और आम तौर पर निवेश शोध और निर्णय लेने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) उन निवेशों को संदर्भित करता है जो विदेशी व्यक्ति, संस्थागत निवेशक या निधियों द्वारा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्युचुअल फंड्स और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे वित्तीय उपकरणों में किए जाते हैं। एफपीआई उन कंपनियों के प्रबंधन या निर्णय लेने में भाग नहीं लेते, जिनमें वे निवेश करते हैं और सामान्यतः इन्हें निष्क्रिय निवेशक माना जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) व्यापार योग्य ऋण उपकरण होती हैं जिन्हें सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, और बाजार में तरलता नियंत्रित करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय समाधान बैंक **(बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस)** एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व में है। यह विश्व के केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए एक बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है।

कराधान में कौन-से बदलाव हुए

हाल के सुधार से पहले, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), जिनमें सेबी-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) शामिल थे, को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 210 के तहत कर लगाया जाता था। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश से अर्जित कोई भी आय कराधान के अधीन थी।

विशेष रूप से:

- एफआईआई/एफपीआई के लिए जी-सेक पर अर्जित ब्याज आय पर 20% कर लगाया जाता था।
- जी-सेक की बिक्री से उत्पन्न अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर, लेनदेन की प्रकृति के अनुसार, 30% कर लगता था।
- दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ पर 12.5% कर लगाया जाता था।
- परिणामस्वरूप, विदेशी निवेशकों द्वारा जी-सेक को रखने या व्यापार करने से अर्जित आय का एक हिस्सा भारत में कर के रूप में देय होता था।

नयी कर व्यवस्था

वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने में एक प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था के महत्व को मान्यता देते हुए, सरकार ने जी-सेक में निवेश करने वाले एफपीआई/एफआईआई के लिए कर छूट की पेशकाश की है।

नयी व्यवस्था के तहत, एफपीआई/एफआईआई निम्नलिखित से मुक्त होंगे:

- जी-सेक से अर्जित ब्याज आय; और
- जी-सेक की बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय या वापसी से उत्पन्न पूँजीगत लाभ।

NEW TAX RATES ON FPI INVESTMENT IN
G-SEC

Income Type	Previous Tax Rate	New Tax Rate
Interest Income from Securities	20%	NIL
Short-Term Capital Gains (STCG)	30%	NIL
Long-Term Capital Gains (LTCG)	12.5%	NIL

Source: Ministry of Finance

यह छूट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद उत्पन्न होने वाली आय पर लागू होगी। आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 में जी-सेक में निवेश करने वाले एफआईआई को यह छूट देने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गये हैं।

पूंजीगत लाभ का वर्गीकरण

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) तब उत्पन्न होते हैं, जब किसी सरकारी प्रतिभूति को निर्धारित स्वामित्व अवधि से अधिक समय तक रखा जाता है।

- सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ: 12 महीने से अधिक।
- असूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ: 24 महीने से अधिक।

अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) तब उत्पन्न होते हैं जब किसी सरकारी प्रतिभूति को निर्धारित स्वामित्व अवधि से कम समय के लिए रखा जाता है।

- सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ: 12 महीने तक।
- असूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ: 24 महीने तक।

सरकारी प्रतिभूति बाजार सुधार

विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी प्रतिभूति में सामान्य मार्ग और पूरी तरह से पहुँच मार्ग (एफएआर) जैसे मार्गों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। सामान्य मार्ग विदेशी निवेशकों के लिए मानक चैनल है। यह उन्हें अनुमति प्राप्त भारतीय जी-सेक खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे किसी विशेष प्रतिभूति में कितना निवेश किया जा सकता है, इसे कितने समय तक रखा जाना चाहिए, और कुल निवेश की सीमा। एफएआर एक खुली-पहुँच वाला चैनल है, जहां विदेशी निवेशक सामान्य मार्ग के तहत लागू प्रतिबंधों के बिना चयनित जी-सेक में निवेश कर सकते हैं।

12 मई 2026 तक, एफपीआई के पास ₹3,75,171 करोड़ मूल्य के जी-सेक थे, जो कुल निर्गत जी-सेक स्टॉक ₹112.42 लाख करोड़ का 3.34% है। गौरतलब है कि इन निवेशों में अधिकांश का योगदान एफएआर ने दिया, जिसमें एफपीआई स्वामित्व **₹3.21 लाख करोड़** था, जो एफएआर के तहत पात्र ₹47.63 लाख करोड़ के निर्गत स्टॉक का 6.74% है।

सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश (12 मई 2026 तक)

मार्ग	एफपीआई स्वामित्व	बकाया स्टॉक	**हिस्सेदारी**
सामान्य मार्ग	₹54,091 करोड़	₹64.78 लाख करोड़	0.83%
एफएआर	₹3,21,080 करोड़	₹47.63 लाख करोड़	6.74%
कुल	₹3,75,171 करोड़	₹112.42 लाख करोड़	3.34%

मजबूत निवेशक रुचि की पहचान करते हुए, सरकार ने एफएआर के दायरे का विस्तार करने और जी-सेक बाजार में विदेशी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अन्य सुधार पेश किए हैं।

पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफएआर) का विस्तार

सरकार ने अब एफएआर के अंतर्गत पात्र प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार किया है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए विभिन्न जी-सेक में निवेश के अवसर बढ़ गए हैं।

एफएआर फ्रेमवर्क में अब शामिल होगा:

- 15 साल के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गम;
- 30-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गम;
- 40-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गम; और
- एफएआर -के योग्य अवधि में जारी किए गए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (एसजीआरबीएस)।

इस विस्तार से परिपक्वता अवधि में निवेश अवसरों के विस्तार होने और लंबी अवधि के सॉवरेन ऋण उपकरणों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सामान्य मार्ग के तहत निवेश प्रतिबंधों में रियायत

सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित प्रतिबंधों को हटा दिया है:

- अल्पकालिक निवेश सीमा;
- संकेंद्रण सीमा; और
- सरकारी प्रतिभूति-वार निवेश सीमा।

हालांकि, कुल निवेश सीमाएं अपरिवर्तित हैं:

- केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लंबित स्टॉक का 6%; और
- राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के लंबित स्टॉक का 2%।

इसके अलावा, एफपीआई निवेशों के लिए मौजूदा 'सामान्य' और 'दीर्घकालिक' श्रेणियां क्रमशः सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए एक ही निवेश सीमा में शामिल कर दी जाएंगी।

सुदृढ़, वैश्विक रूप से अधिक एकीकृत पूंजी बाजारों की ओर

बाजार की पहुंच को सरल बनाकर और संचालन जटिलताओं को कम करके, ये उपाय सहज निवेश अनुभव प्रदान करेंगे, जो प्रमुख वैश्विक बाजारों के अनुरूप होगा। समय के साथ, उम्मीद की जाती है कि ये उपाय भारतीय बॉन्ड्स को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करने, दीर्घकालिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने, ऋण और इक्विटी बाजार, दोनों में भागीदारी बढ़ाने और भारत की वित्तीय प्रणाली को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक एकीकृत करने में सहयोग करेंगे। ये सुधार उन वैश्विक निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे जो दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक में अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

संदर्भ

वित्त मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2269169&reg=48&lang=2

https://x.com/finminindia/status/2062769417390588095?s=48&t=CSE0glwGSDCXRHUtG7cLjw

विधि एवं न्याय मंत्रालय

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jun/doc202665883801.pdf

भारतीय रिजर्व बैंक

https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/FAQs.aspx?Id=711#1

पीआईबी अनुसंधान